लोकसभा चुनाव, 2019

दलित वोट : भाजपा क्यों आगे रही?

ज्योति मिश्रा और विभा अत्री

अनुवाद : सताक्षी मालवीय

भारत की कुल जनसंख्या में दलितों का अनुपात 16.6 प्रतिशत है और उसके चार राज्यों में दलितों की आधी जनसंख्या निवास करती है। ये चार राज्य हैं : उत्तर प्रदेश (20.6 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (10.7 प्रतिशत), बिहार (8.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (7.2 प्रतिशत)। उत्तर प्रदेश में संख्यात्मक रूप से सबसे ज़्यादा दलित निवास करते हैं, लेकिन पंजाब की जनसंख्या में दलितों का अनुपात सबसे ज़्यादा है। पंजाब की जनसंख्या का कुल 31.9 प्रतिशत हिस्सा दलितों का है। दलितों की संख्यात्मक स्थिति चुनावी राजनीति में उन्हें एक ऐसी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक श्रेणी बना देती है कि कोई भी राजनीतिक दल उनके हितों की उपेक्षा करके चुनाव नहीं जीत सकता। 1984 में बहुजन समाज पार्टी के गठन से पहले कोई भी ऐसा अखिल भारतीय दल नहीं था, जिसे दलित पार्टी माना जा सकता हो। इससे पहले इस समुदाय के मतदाता अमूमन कॉन्ग्रेस पार्टी को वोट देते थे। आज़ादी के बाद के दौर में डॉ. भीमराव आंबेडकर ने एक देशव्यापी दलित पार्टी की स्थापना का प्रयास किया। उन्होंने 1956 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया की स्थापना की। लेकिन चुनावी राजनीति में यह पार्टी कोई गहरी छाप नहीं छोड़ नहीं पाई, क्योंकि उसे दलितों के सिर्फ़ कुछ उप-समूहों ने ही अपना समर्थन दिया।[1] जातीय दलों के रूप में वर्णित कई दलों ने स्वयं को इस समुदाय के हित-रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्हें दलित मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर समर्थन भी दिया। कुछ राज्यों में ऐसे क्षेत्रीय दल भी रहे हैं, जिन्होंने अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा करने का

[1] क्रिस्टॉफ़ जैफ़्रलो (2012) : 49-53.

दावा किया है। तमिलनाडु में विदुथलाई चिरूथाईगाल काची (विचिका), महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाले वंचित बहुजन अघाड़ी और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है और उत्तर प्रदेश तथा पंजाब की राजनीति में इसकी मौजूदगी काफ़ी मजबूत है। लोकनीति-सीएसडीएस द्वारा 2019 के राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन के चुनावोपरांत सर्वेक्षण के आँकड़ों से यह संकेत मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दलित मतदाताओं का काफ़ी ज़बर्दस्त समर्थन मिला। दूसरी ओर, भारतीय चुनाव आयोग से मिले आँकड़ों से भी यह संकेत मिलता है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में भाजपा ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। इस अध्याय में दलित मतदाताओं के मत-व्यवहार में इन बदलती प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए अनुसूचित जाति के मतदाताओं के राजनीतिक रुझानों और चुनावी व्यवहार का अध्ययन किया गया है, और इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि इसका चुनावी परिणामों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदर्शन पर कैसा प्रभाव पड़ा।

दलितों का मतदान प्रतिशत

भारत में आज़ादी से पहले के दौर में आंबेडकरवादी आंदोलन आरंभ हुआ। इसने दलितों और समाज के हाशिए पर पड़े अन्य जाति-समूहों को गोलबंद करने का प्रयास किया। इसके ज़रिए इन समूहों को एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक श्रेणी में तब्दील होने का मौक़ा मिला। 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनॉल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवॉर्ड में अन्य सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ दलितों के लिए पृथक् निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। इस प्रावधान का गांधी ने पुरज़ोर विरोध किया, लेकिन आंबेडकर द्वारा इसका ज़ोरदार स्वागत किया गया। बहरहाल, पूना पैक्ट के माध्यम से पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान वापस ले लिया गया, लेकिन प्रांतीय विधायिकाओं और केंद्रीय विधायिका में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी गई।

आज़ादी के बाद के दौर में दलित मतदाताओं को गोलबंद करने के प्रयास किए गए। यह एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को आगे ले जाने की तरह था। सुहास पलशीकर का मानना है कि दलित समुदाय भारतीय समाज के ऐसे पहले समूह थे जिन्होंने सामूहिक कार्रवाई के आधुनिक राजनीतिक साधनों का उपयोग किया, और प्रतियोगी राजनीति में जाति को एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया।[2] यह कारक भारतीय चुनावी व्यवस्था में मतदाताओं के मतदान प्रतिशत की प्रवृत्तियों से भी सामने आता है। यदि हम विभिन्न जाति समुदायों के लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत पर ध्यान दें तो यह बात सामने आती है कि अन्य जाति समुदायों की तुलना में दलितों का मतदान प्रतिशत हमेशा ही ज़्यादा रहा है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में यह प्रवृत्ति पूरी तरह बदल गई, और अन्य समुदायों की तुलना में दलितों का मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा। 2019 के लोकसभा चुनावों में आदिवासी मतदाताओं ने सबसे ज़्यादा मतदान किया। (देखें; रेखा चित्र-1)

[2] सुहास पलशीकर (2007) : 101-129.

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न दलों का प्रदर्शन

दलित भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे। उन्हें मुख्यधारा की राजनीति में लाने और राजनीतिक जीवन में सम्मिलित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की कुल जनसंख्या में उनके अनुपात के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उनके लिए निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाएगा। दलितों के लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों में सिर्फ़ दलित (या अनुसूचित जाति) समुदाय के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। दलितों के लिए कुल मिला कर 84 निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है। इन आरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदर्शन का अध्ययन करने के लिए हमने इन्हें पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया है। यह वर्गीकरण इस प्रकार है : उत्तर-पूर्व : असम; पूर्व : पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड; उत्तर : हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड; पश्चिम-मध्य : गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़; दक्षिण : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना।

2019 में दलितों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन अन्य दलों की तुलना में काफ़ी अच्छा रहा है। पार्टी ने दलितों के लिए आरक्षित कुल 84 निर्वाचन क्षेत्रों में से 46 सीटों पर जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, भाजपा ने सीटों और मत-प्रतिशत — दोनों ही संदर्भों में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। भाजपा की सीटों की संख्या में छह और मत-प्रतिशत में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले अमूमन दलितों का वोट हासिल करने वाली कॉन्ग्रेस ने अपना आधार खो दिया। इसे 2019 के चुनावों में दलितों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में से सिर्फ़ छह सीटों पर जीत मिली। इस लिहाज़ से 2014 की तुलना में इसे एक सीट का नुक़सान हुआ। दलित जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनावों की तुलना में 2019 में अपने प्रदर्शन में सुधार किया। 2014 के लोकसभा चुनावों में बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, 2019 में इसे दलितों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में से दो सीटों पर जीत मिली, और इसके मत-प्रतिशत में भी हल्की-फुल्की वृद्धि हुई। यदि हम अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में ऊपर वर्णित विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं तो यह बात सामने आती है कि भाजपा ने पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। पूर्वी क्षेत्र में दलित समुदाय के लिए कुल 20 आरक्षित सीटें हैं। इन 20 सीटों में भाजपा ने सात सीटों पर जीत हासिल की और इसे कुल 35.4 प्रतिशत मत मिले, जो 2014 के चुनावों में मिले मतों से 17.7 प्रतिशत ज़्यादा थे। भाजपा ने मुख्य रूप से, पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के मतों में सेंध लगाते हुए अपने मत में वृद्धि की। 2019 के चुनावों में पूर्वी क्षेत्र में वामपंथी दलों को कुल मिला कर 15.36 प्रतिशत मतों का नुक़सान हुआ, और इसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में सिर्फ़ 3.75 प्रतिशत मत ही मिले। यद्यपि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए सिर्फ़ असम राज्य में एक सीट आरक्षित थी, फिर भी भाजपा को 2014 के चुनावों की तुलना में 15.22 प्रतिशत ज़्यादा मत मिले। (देखें, तालिका-1)

रेखाचित्र-1

विभिन्न लोकसभा चुनावों में विविध जाति समूहों का मतदान प्रतिशत
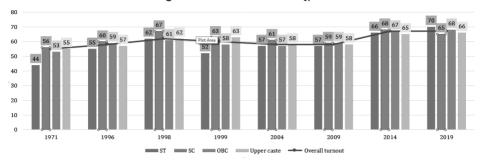
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित क्षेत्रों से केवल दलित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सभी समुदाय के लोग वोट डालते हैं। इसलिए यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि क्या भाजपा को दलित मतदाताओं से भी वैसा ही समर्थन मिला जैसा कि ग़ैर-दलित मतदाताओं से मिला। सीएसडीएस द्वारा संकलित चुनाव के बाद के सर्वेक्षण आँकड़ों से यह संकेत मिलता है कि सामान्य जातियों के 20 प्रतिशत मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया, वहीं 25 प्रतिशत से कुछ ज़्यादा मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया। इन क्षेत्रों में एक-तिहाई से कुछ ज़्यादा मतदाताओं ने क्षेत्रीय दलों को वोट दिया (तालिका-2)। तालिका-3 में संसदीय क्षेत्रों में दलित समुदाय की जनसंख्या में भागीदारी, और इन क्षेत्रों में दलों के सीट और वोट में हिस्सेदारी को दिखाया गया है। इन आँकड़ों से पता चलता है कि भाजपा ने उन संसदीय क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया, जहाँ दलितों की जनसंख्या 10 प्रतिशत से कम थी। इसके विपरीत, भाजपा का मत-प्रतिशत उन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में गिरा, जहाँ दलितों की जनसंख्या 20 प्रतिशत से ज़्यादा थी। इन निर्वाचन क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा।

अनुसूचित जातियों के मत-व्यवहार का स्वरूप

कॉन्ग्रेस के प्रभुत्व के दौर में कॉन्ग्रेस को दलितों के मतों का बड़ा हिस्सा मिलता था। लेकिन दलीय व्यवस्था और चुनावी राजनीति में बदलाव के साथ कॉन्ग्रेस को मिलने वाले दलितों के मतों में गिरावट आई। अस्मिता की राजनीति के दौर में नए राजनीतिक दलों का उभार हुआ। इन दलों ने ख़ुद को दलित पार्टियों के रूप में प्रस्तुत किया। इनके उदय के कारण दलितों के मत-व्यवहार में भी बदलाव आया। मसलन, 1960 के दशक के आख़िरी वर्षों में और 1970 के दशक में रिपब्लिकन पार्टी के उदय के कारण कॉन्ग्रेस और उसके बीच दलित मतों का बँटवारा हुआ। इसी तरह 1977 के बाद दलितों का मत कॉन्ग्रेस और जनता पार्टी (बाद में जनता दल) के बीच विभाजित होने लगा। बसपा के उदय के बाद दलित मतदाताओं ने बहुत से राज्यों में इसे वोट देना आरंभ कर दिया। बसपा के गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्तर पर इसे औसतन चार प्रतिशत मत मिल रहे थे, लेकिन दलित मतदाताओं के बीच इसका समर्थन बहुत ज़्यादा था। 1996 के लोकसभा चुनावों के दौरान तक़रीबन एक-चौथाई दलित मतदाताओं ने बसपा का साथ दिया था। इसके बाद, 2014 के चुनावों तक

तालिका-1

2019 में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों में विभिन्न दलों का प्रदर्शन : 2014 की तुलना में बदलाव

क्षेत्र	कुल सीट	कॉन्ग्रेस		भाजपा		वाम-दल		बसपा		अन्य	
		जीत	मत (%)	जीत	मत (%)	जीत	मत (%)	जीत	मत (%)	जीत	मत (%)
उत्तर-पूर्व	1	0 (0)	11.36 (-14.18)	1 (1)	44.62 (15.22)	0 (0)	0.15 (0.15)	0 (0)	0 (0)	0 (-1)	43.87 (-1.19)
पूर्व	20	0 (0)	5.71 (-5.23)	7 (3)	35.4 (17.72)	0 (0)	3.75 (-15.36)	0 (0)	1.25 (0.25)	13 (-3)	53.89 (2.62)
उत्तर	26	3 (2)	13.48 (0.47)	20 (-2)	45.07 (7.61)	0 (0)	0.18 (-0.21)	2 (2)	18.25 (2.07)	1 (-2)	23.02 (-9.49)
पश्चिम-मध्य	16	0 (0)	32.77 (1.38)	13 (0)	47.51 (1.49)	0 (0)	0.27 (0.04)	0 (0)	2.16 (-1.29)	3 (0)	17.29 (-1.62)
दक्षिण	21	3 (-3)	20.08 (0.44)	5 (4)	14.5 (1.83)	0 (1)	5.27 (1.11)	0 (0)	1.23 (0.46)	12 (-1)	58.92 (-3.84)
कुल	**84**	**6 (-1)**	**16.74 (-0.86)**	**46 (6)**	**35.34 (7.72)**	**1 (0)**	**2.4 (-3.69)**	**2 (2)**	**6.31 (0.4)**	**29 (-7)**	**39.21 (-3.57)**

स्रोतः सीएसडीएस डेटा यूनिट द्वारा संकलित भारतीय चुनाव आयोग के आँकड़े.

तालिका-2

2019 में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर जाति समूह के आधार पर मत-व्यवहार का स्वरूप (प्रतिशत में)

	कॉन्ग्रेस	भाजपा	बसपा	वाम दल	अन्य
अनुसूचित जाति	20	28	12	5	36
अनुसूचित जनजाति	34	28	3	4	31
अन्य पिछड़े वर्ग	13	30	4	4	49
अन्य	15	40	3	6	37
कुल	**16**	**32**	**6**	**5**	**41**

स्रोतः सीएसडीएस द्वारा संचालित राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन-2019.

तालिका-3

अनुसूचित जाति श्रेणी के अनुसार नतीजे

अनुसूचित जाति जनसंख्या	कुल सीट	कॉन्ग्रेस		भाजपा		बसपा +		अन्य	
		जीत	मत (%)	जीत	मत (%)	जीत	मत (%)	जीत	मत (%)
10 %	124	17	26.76	68	38.13	0	0.8	39	34.31
10-19.9 %	273	24	18.95	152	37.3	7	5.71	90	38.04
20-29.9 %	117	6	15.28	68	37.69	8	12.72	35	34.31
30 % और उससे ज़्यादा	28	5	13.38	15	33.56	0	10.79	8	42.27
कुल	**542**	**52**	**19.49**	**303**	**37.36**	**15**	**6.48**	**172**	**36.67**

स्रोत : सीएसडीएस डेटा यूनिट द्वारा संकलित भारतीय चुनाव आयोग के आँकड़े.

तक़रीबन बीस प्रतिशत दलित मतदाता बसपा को अपना मत देते रहे। 2014 के लोकसभा चुनावों में और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में दलित मतदाताओं के बीच बसपा के समर्थन में गिरावट आई। 2014 के लोकसभा चुनावों से ही भाजपा ने दलित मतदाताओं में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। इन चुनावों के दौरान बहुत से राज्य स्तरीय दलों को भी दलितों का वोट मिला। 2009 के लोकसभा चुनावों की तुलना में 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को दलितों को तक़रीबन दोगुना मत मिला। 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा को दलितों के 12 प्रतिशत मत मिले थे। लेकिन 2014 के चुनावों में भाजपा को दलितों के 24 प्रतिशत मत मिले। रोचक है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में दलितों के बीच भाजपा के मतों में दस प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन चुनावों में 34 प्रतिशत दलितों ने भाजपा को मत दिया। यह काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अपने पहले कार्यकाल में कई कारणों से दलितों के असंतोष का सामना करना पड़ा। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निषेध अधिनियम क़ानून का मसला और स्थानीय स्तर पर दलितों के ख़िलाफ़ हो रही जातिगत हिंसा का मसला प्रमुख था। लेकिन दलितों के बीच भाजपा के प्रदर्शन से यह संकेत मिलता है कि भाजपा ने दलित मतदाताओं के असंतोष को शांत करने में सफलता प्राप्त कर ली थी।[3] तालिका-4 का गहराई से अध्ययन करने पर यह संकेत मिलता है कि भाजपा ने मुख्य रूप से वामपंथी दलों और क्षेत्रीय दलों के दलित मतदाताओं को अपनी तरफ़ खींचा है। 2019 में भी कॉन्ग्रेस के पास दलितों का 2014 जितना ही समर्थन रहा। असल में, उसे केवल एक प्रतिशत का ही फ़ायदा हुआ।

तालिका-5 में यह दिखाया गया है कि 2014 और 2019 के बीच दलों ने अपने दलित मतों को किस सीमा तक बरक़रार रखा है। इस संदर्भ में बसपा का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है। 2014 में बसपा को मत देने वाले 80 प्रतिशत लोगों ने 2019 में भी बसपा को ही मत दिया। भाजपा और कॉन्ग्रेस — दोनों ने अपने सहयोगियों के साथ 2014 की तुलना में 2019 में तीन-चौथाई मतों को क़ायम रखा। ये आँकड़े ऊपर वर्णित इस तर्क का भी अनुमोदन करते हैं कि भाजपा ने वाम दलों और क्षेत्रीय दलों की क़ीमत पर दलितों के बीच अपनी स्थिति मज़बूत की है। तालिका-5 से यह बात सामने आती है कि 2014 में वाम दलों के एक-तिहाई मतदाताओं ने 2019 में भाजपा को मत दिया। इसी तरह, 2014 में क्षेत्रीय दलों को मतदान करने वाले 28 प्रतिशत दलित मतदाताओं ने 2019 में भाजपा को वोट दिया।

दलित मतदाताओं की सामाजिक और आर्थिक हैसियत ने भी मतदान के लिए उनके द्वारा दलों के चयन को प्रभावित किया। तालिका-6 से यह संकेत मिलता है कि भाजपा ने हर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले मतदाताओं को प्रभावित किया। जब हम जेंडर के आधार पर विश्लेषण करते हैं, तो यह पाते हैं कि 2014 की तरह ही 2019 में दलित पुरुषों और महिलाओं के बीच भाजपा के मत प्रतिशत में वृद्धि हुई। रोचक बात यह है कि बसपा की कमान एक महिला के हाथ में होने के बावजूद महिलाओं के बीच बसपा के मतों में पाँच प्रतिशत की गिरावट हुई। पुरुष भी बसपा से दूर हुए, लेकिन इनके मतों में दो प्रतिशत की ही गिरावट हुई। दलित मतदाताओं के वर्ग के आधार पर विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि भाजपा ने 2014 के चुनावों की तुलना में इन चुनावों में ग़रीब, निम्न और उच्च वर्ग के दलितों के बीच अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन 2014 की तुलना में दलित

[3] देखें, संजय कुमार और प्रणव गुप्ता (2019).

तालिका-4

अनुसूचित जातियों का मत-व्यवहार : 1971-2009 (प्रतिशत में)

वर्ष	कॉन्ग्रेस	भाजपा	वाम दल	बसपा	अन्य
1971	46	0	17	- - -	27
1996	34	14	11	7	34
1998	28	14	4	23	31
1999	30	14	11	18	27
2004	27	13	10	19	31
2009	27	12	11	20	30
2014	19	24	6	14	37
2019	20	34	2	11	33

नोट : इन लोकसभा चुनावों में दलों के वास्तविक मत से आँकड़ों को भारित किया गया है। 1971 में जनसंघ के मत प्रतिशत को भाजपा के स्तंभ में ही वर्णित किया गया है. इस समय भाजपा का अस्तित्व नहीं था।

स्रोत : सीएसडीएस द्वारा संचालित राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन.

मध्य वर्ग में इसके मतों में एक प्रतिशत की गिरावट हुई। 2019 में दलित मतदाताओं के मतदान-स्वरूप की व्याख्या करते हुए बद्री नारायण ने यह विचार व्यक्त किया है कि दलित युवा भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा की गई ग़ैर-दलित गतिविधियों से प्रभावित हुए थे।[4] यह मध्य वर्ग के दलित मतदाताओं द्वारा भाजपा को वोट न देने का एक संभावित कारण हो सकता है। जहाँ उच्च वर्ग से जुड़े दलित मतदाता बसपा से दूर हो गए। मसलन, 2014 के लोकसभा चुनावों में उच्च वर्ग के 20 प्रतिशत दलित मतदाताओं ने बसपा के पक्ष में मतदान किया था, वहीं 2019 में यह संख्या घट कर 2 प्रतिशत रह गई। बहरहाल, कॉन्ग्रेस ने भी 2014 की तुलना में मध्य और उच्च वर्ग के दलितों के बीच अच्छा प्रदर्शन किया था। दलित मतदाताओं के निवास का क्षेत्र भी उनके मतदान की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दलितों के बीच अपने समर्थन को बढ़ाया, वहीं कॉन्ग्रेस ने शहरी दलितों के बीच अच्छा प्रदर्शन किया। (तालिका-6)।

राज्य स्तर पर दलित मतदाताओं का मत-व्यवहार

विभिन्न राज्यों में दलित मतदाताओं के मत-व्यवहार का परीक्षण करने से कुछ रोचक प्रवृत्तियाँ सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा अपने मुख्य मतदाता — जाटव समूह के सबसे बड़े हिस्से पर क़ब्ज़ा क़ायम रखने में सफल रही। यहाँ 2019 के लोकसभा चुनावों में तीन-चौथाई से भी ज़्यादा जाटव

[4] बद्री नारायण (2019).

तालिका-5
2014 और 2019 के चुनावों के बीच दलित मतदाताओं के मतदान में बदलाव

2014 में वोट प्राप्त करने वाले दल	2019 में वोट प्राप्त करने वाले दल						
	कॉन्ग्रेस	कॉन्ग्रेस के सहयोगी	भाजपा	भाजपा के सहयोगी	बसपा	वाम दल	अन्य
कॉन्ग्रेस	70	7	12	2		1	7
कॉन्ग्रेस के सहयोगी	20	65	10	- -	- -	1	3
भाजपा	9	3	62	10		0	9
भाजपा के सहयोगी	4	17	22	49	- -	- -	8
बसपा	3	1	7	- -		1	7
वाम दल	6	- -	33	- -	- -	45	16
अन्य	3	- -	28	- -	4	1	64

स्रोत: सीएसडीएस द्वारा संचालित राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन.

मतदाताओं ने बसपा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के महागठबंधन को अपना मत दिया। लेकिन ग़ैर-जाटव दलित मतदाताओं ने अलग तरीक़े से वोट डाले। इन समूहों के बीच भाजपा के मत-प्रतिशत में वृद्धि हुई। बिहार में कॉन्ग्रेस को चमारों और अन्य अनुसूचित जातियों के बीच नुक़सान का सामना करना पड़ा। जनता दल (यूनाइटेड) के पास पहले से ही अत्यंत पिछड़ी जातियों का समर्थन था, इसे दलितों के भी काफ़ी वोट मिले। इसके गठबंधन सहयोगी भाजपा को भी इस समूह से लाभ हुआ। इस तबक़े को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नीतीश कुमार ने महादलित श्रेणी का निर्माण किया। इससे महादलितों के बीच इन पार्टियों का प्रभाव बढ़ा। असल में, महादलित श्रेणी के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य दलितों के बीच सबसे ग़रीब और सबसे कमज़ोर जातियों की सहायता करना था।[5] किंतु 2019 का चुनाव नज़दीक आने पर नीतीश कुमार ने दलित और महादलित के बीच के भेद को ख़त्म कर दिया। उन्होंने यह घोषणा की कि महादलित विकास मिशन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सभी अनुसूचित जातियों को मिलेगा।[6] निश्चित रूप से, यह दलित मतदाताओं को अपने गठबंधन की ओर खींचने के लिए एक दलित केंद्रित रणनीति थी। चूँकि इस गठबंधन में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी सम्मिलित थी, इसलिए पासवान जाति को भी महादलित की श्रेणी में शामिल कर लिया गया, जो पहले इस श्रेणी से बाहर थी।

पश्चिम बंगाल में राजवंशियों, नामशूद्रों और अन्य दलित जातियों के बीच भाजपा के मत-

---
[5] सुरूर अहमद (2018).

[6] अमिताभ श्रीवास्तव (2018).

तालिका-6
सामाजिक-आर्थिक हैसियत के अनुसार दलितों का मत-व्यवहार

	कॉन्ग्रेस		भाजपा		बसपा		वाम दल		अन्य	
	2019	**2014**	**2019**	**2014**	**2019**	**2014**	**2019**	**2014**	**2019**	**2014**
पुरुष	20	21	35	28	12	14	2	4	32	32
महिला	20	21	32	25	10	15	3	4	36	35
ग़रीब	14	19	34	25	14	14	3	5	35	37
निम्न	23	21	35	25	10	15	2	6	31	33
मध्य	26	22	29	30	10	13	2	3	33	33
अमीर	23	19	36	28	2	20	1	3	39	30
ग्रामीण	17	21	35	25	13	15	3	5	34	33
शहरी	30	20	30	31	6	12	1	3	33	34

स्रोत: सीएसडीएस द्वारा 2014 और 2019 में संचालित राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन.

प्रतिशत में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। भाजपा ने तृणमूल कॉन्ग्रेस और वाम दलों के वोटों में कटौती करके अपने समर्थन आधार में वृद्धि की। आँकड़ों से यह बात सामने आती है कि राजवंशियों के बीच तृणमूल कॉन्ग्रेस के मतों में 25 प्रतिशत और नामशूद्र के बीच सात प्रतिशत की गिरावट हुई। तृणमूल कॉन्ग्रेस की सरकार ने राजवंशियों और नामशूद्रों के लिए विकास और सांस्कृतिक बोर्डों का गठन किया था। इस संदर्भ में यदि तृणमूल के समर्थन में गिरावट पर विचार करें तो यह बात सामने आती है कि ऊपर से संचालित होने वाले विकास के कार्यक्रम विभिन्न समुदायों की आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में नाकाम रहते हैं।[7] यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि भाजपा ने ममता बनर्जी के दलित वोट बैंक में सेंध लगाई है। इसका एक प्रमाण है कि यह कि राज्य में दलितों के लिए आरक्षित दस सीटों में से पाँच सीटों पर भाजपा को जीत मिली है।

तमिलनाडु में द्रमुक और कॉन्ग्रेस ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। इन्होंने दलितों के बीच अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली। एक ओर, कॉन्ग्रेस को आदि द्रविड़ों के समर्थन में काफ़ी वृद्धि हुई, वहीं द्रमुक को अन्य अनुसूचित जातियों के समर्थन से लाभ मिला। पंजाब की कुल जनसंख्या में तक़रीबन 32 प्रतिशत दलित हैं। बसपा का आरंभ यहीं से हुआ था। 2019 के चुनावों में इसे पिछले चुनाव की तुलना में दलितों का 16 प्रतिशत ज़्यादा मत मिला। असल में, आम आदमी पार्टी के वोटों

[7] ज्योतिप्रसाद चटर्जी और सुप्रियो बसु (2019) : 16-19.

की क़ीमत पर इसे लाभ हुआ। उसके दलित वोटों में 14 प्रतिशत की गिरावट हुई। इसके साथ ही, पिछले चुनावों की तुलना में कॉन्ग्रेस को मिलने वाले दलितों के मतों में भी 6 प्रतिशत की गिरावट हुई।

दलितों ने भाजपा को मत क्यों दिया?

2019 के लोकसभा चुनावों से पहले यह माना जाता था कि दलित विरोधी घटनाओं के कारण दलितों का भाजपा से मोह भंग हो गया है। ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निषेध) अधिनियम के प्रावधानों को कमज़ोर करने, रोहित वेमुला की आत्महत्या, महाराष्ट्र में भीमा कोरेगाँव की घटना और ऊना में दलितों की पिटाई की घटना प्रमुख थी। यह माना जाता था कि दलित मतदाता भाजपा का वोट नहीं देंगे क्योंकि भाजपा सरकार द्वारा दलितों के हितों की सुरक्षा नहीं की गई। लेकिन इन अनुमानों के विपरीत भाजपा को मिलने वाले दलितों के मत-प्रतिशत में वृद्धि हुई, और पिछली बार की तुलना में उसे इन मतदाताओं का 10 प्रतिशत ज़्यादा वोट मिला। इसलिए उन संभावित कारणों की पड़ताल करना आवश्यक है जिसके कारण दलितों ने 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को मत दिया। इस भाग में भाजपा को दलितों के ज़्यादा वोट मिलने के कुछ कारणों को रेखांकित किया गया है। पहला कारण यह हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने ग़रीबों को ध्यान में रखते हुए कुछ कल्याणकारी योजनाएँ आरंभ की थीं। भारत में दलित मोटे तौर पर ग़रीबों की श्रेणी में ही आते हैं। भाजपा ने मुख्य रूप से ग़ैर-प्रभुत्वशाली और छोटे दलित समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया। इसने उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से इन समुदायों को लाभ पहुँचाने का प्रयत्न किया। इसके चलते दलित समुदायों में हाशिए के समुदाय इसकी ओर आकृष्ट हुए, और उन्होंने दलितों की प्रभुत्वशाली जातियों से अलग हटते हुए भाजपा को मत दिया। तालिका-8 में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न सामाजिक योजनाओं का लाभ हासिल करने वाली जातियों के बारे में बताया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि दलितों और आदिवासियों में हाशिये के समूहों को इन योजनाओं से ज़्यादा लाभ हुआ। आँकड़ों से यह बात भी सामने आती है कि जिन दलितों को इन योजनाओं का लाभ मिला, उन्होंने इन योजनाओं का लाभ न पाने वाले दलितों की तुलना में भाजपा को ज़्यादा वरीयता दी। (तालिका-9)

दलितों के बीच भाजपा का समर्थन बढ़ने का दूसरा कारण उनके बीच हिंदुत्व की राजनीति और अल्पसंख्यक विरोधी भावनाओं का प्रसार है। श्रेयस सरदेसाई ने तर्क दिया है कि अल्पसंख्यक विरोधी भावनाओं के कारण भी हिंदू मतदाता मोदी के नेतृत्व वाले राजग के पीछे गोलबंद हुए हैं।[8] भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के नेतृत्व में पिछले पाँच वर्षों में जो राजनीतिक उथल-पुथल हुई है, उसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम हिंदुत्व की राजनीति पर ध्यान दें। इसने भारत के मतदाताओं को हिंदुत्व के नाम पर विभाजित किया है और इसने जाति की राजनीति के ऊपर धर्म की पहचान को स्थापित करने का काम किया है। भाजपा ने दलित समुदायों को तुष्ट करने के लिए जी-तोड़ मेहनत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफ़ाईकर्मियों के पैर धोए। यहाँ तक कि संघ ने भी दलित समुदाय में सबसे वंचित तबक़ों के बीच काम किया। इसने बहुत से सम्मेलनों को आयोजित

[8] श्रेयस सरदेसाई (2019).

तालिका-7
2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राज्यों में दलितों के मतदान की प्रवृत्ति (प्रतिशत)

राज्य	प्रभुत्वशाली अनुसूचित जाति समूह	कॉन्ग्रेस	भाजपा	क्षेत्रीय दल
बिहार	चमार (46)	(-7)	20 (2)	राजद 2 (-6) जद (यू) 38 (+22) अन्य दल 40 (-11)
	अन्य अनुसूचित जातियाँ (69)	(-2)	36 (2)	राजद 4 (-2) जद (यू) (21) अन्य दल 19 (-19)
उत्तर प्रदेश	जाटव (289)	1 (-1)	17 (0)	बसपा 46 (-24) सपा 28 (23) अन्य दल 8 (1)
	अन्य अनुसूचित जातियाँ (171)	7 (+3)	49 (+7)	बसपा 23 (-7) सपा 18 (6) अन्य दल 3 (-9)
पंजाब	सभी अनुसूचित जातियाँ (221)	38 (-6)	11 (2)	अकाली दल 22 (4) बसपा 18 (16) आप 7 (-14) अन्य दल 4 (-3)
तमिलनाडु	आदि द्रविडार (122)	12 (+12)*	4 (+4)	अन्नाद्रमुक 16 (-42) द्रमुक 25 (8) अन्य दल 43 (18)
	अन्य अनुसूचित जातियाँ (136)	8 (4)	8 (85)	अन्नाद्रमुक 9 (-32) द्रमुक 55 (31) अन्य दल 20 (-7)
पश्चिम बंगाल	राजबंशी(122)	9 (1)	75 (48)	तृणमूल कॉन्ग्रेस 9 (-25) वाम दल 4 (-25) अन्य दल 3 (1)
	नामशूद्र (129)	2(-4)	58 (36)	तृणमूल कॉन्ग्रेस 35 (-7) वाम दल 4 (-27) अन्य दल <0 (0)
	अन्य अनुसूचित जातियाँ (140)	1 (-7)	52 (35)	तृणमूल कॉन्ग्रेस 37 (5) वाम दल 8 (-21)
				अन्य दल 2(-2)

स्रोत: सीएसडीएस द्वारा 2014 और 2019 में संचालित राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन.

तालिका-8

विभिन्न जाति-समुदायों में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी (प्रतिशत में)

	पीएम आवास योजना	आयुष्मान	पेंशन	पीडीएस	उज्ज्वला योजना
उच्च जाति	14	15	23	38	31
अन्य पिछड़ी जाति	21	17	27	46	35
अनुसूचित जाति	26	20	26	50	38
अनुसूचित जनजाति	38	24	30	52	52
मुस्लिम	20	16	23	44	31
अन्य	16	14	26	38	24
सभी लाभार्थी	21	17	26	45	35

स्रोतः सीएसडीएस द्वारा संचालित 2019 का राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन.

करके इन जातियों के नेताओं को हिंदुत्व से जोड़ने का प्रयास किया। हिंदुत्व की राजनीति के दलितों के मतदान पर प्रभाव को समझने के लिए अल्पसंख्यकों के बारे में उनके विचार की एक समग्र सूची तैयार की गई।[9] तालिका-10 से यह बात सामने आती है कि अन्य जाति समुदायों की तुलना में

[9] अल्पसंख्यकों के बारे में दृष्टिकोण की समग्र सूची तैयार करने के लिए पाँच प्रश्न पूछे गये : (1) आप इन दो कथनों में से किससे सहमत हैं — पहला, भारत प्राथमिक रूप से सिर्फ़ हिंदुओं से संबंधित है, दूसरा, भारत सिर्फ़ हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए है. (2) आपके अनुसार, हिंदू समुदाय कितना राष्ट्रवादी है — बहुत ज़्यादा, कुछ हद तक, कुछ ख़ास नहीं या बिल्कुल नहीं. (3) आपके अनुसार मुस्लिम समुदाय कितना राष्ट्रवादी है — बहुत ज़्यादा, कुछ हद तक, कुछ ख़ास नहीं या बिल्कुल नहीं. (4) आपके अनुसार ईसाई समुदाय कितना राष्ट्रवादी है — बहुत ज़्यादा, कुछ हद तक, कुछ ख़ास नहीं या बिल्कुल नहीं। आप निम्नलिखित कथन से सहमत हैं, या असहमत — भले ही इसे बहुमत पसंद न करे, सरकार को अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करनी चाहिए. पहले प्रश्न में दूसरे कथन के लिए 2 और पहले कथन के लिए 1 अंक तय किया गया. प्रश्न 2, 3, और 4 में जिन लोगों ने 'बहुत ज़्यादा' या 'कुछ हद तक' कहा उन्हें 2 अंक दिए गए, और जिन्होंने 'कुछ ख़ास नहीं' या 'बिल्कुल नहीं' कहा, उन्हें 1 अंक दिया गया. प्रश्न 5 में जिन लोगों ने कथन के साथ सहमति व्यक्त की (या तो दृढ़ता से या कुछ हद तक) उन्हें 2 अंक दिये गये, और जिन लोगों ने असहमति व्यक्त की, उन्हें 1 अंक दिया गया. जिन लोगों ने सभी 5 प्रश्नों पर कोई राय नहीं दी, उसे 0 अंक दिया गया. अंतिम परिणाम के रूप में 0 से 10 के बीच अंक आए। इन अंकों को पाँच नयी श्रेणियों में वितरित किया गया, जो उत्तरदाताओं के अल्पसंख्यक-विरोधी या अल्पसंख्यक-समर्थक दृष्टिकोण की गहनता दर्शाते थे. जिन लोगों को 9 और 10 के बीच अंक मिला, उन्हें 'अत्यधिक अल्पसंख्यक-समर्थक' माना गया. जिन्हें 6 से 8 के बीच अंक मिले उन्हें 'अल्पसंख्यक-समर्थक' माना गया. जिन लोगों को 3 से 5 के बीच अंक मिले उन्हें अल्पसंख्यक-विरोधी माना गया. इसके अलावा, जिन्हें 1 और 2 के बीच अंक मिले उन्हें 'अत्यधिक अल्पसंख्यक-

तालिका-9

ग़ैर-दलित लाभार्थियों की तुलना में अन्य लाभार्थियों ने भाजपा को ज़्यादा वरीयता दी (प्रतिशत में)

	कॉन्ग्रेस	कॉन्ग्रेस के सहयोगी	भाजपा	भाजपा के सहयोगी	बसपा और सहयोगी	वाम दल	अन्य
आवास योजना							
लाभार्थी	21	8	35	9	9	4	15
ग़ैर-लाभार्थी	20	5	33	6	12	2	23
आयुष्मान योजना							
लाभार्थी	17	12	40	7	6	3	14
ग़ैर-लाभार्थी	21	4	32	7	12	2	23
पीडीएस							
लाभार्थी	20	6	34	7	11	2	21
ग़ैर-लाभार्थी	20	5	32	5	11	3	24
उज्ज्वला योजना							
लाभार्थी	19	5	39	6	11	2	18
ग़ैर-लाभार्थी	20	6	30	8	11	3	23

स्रोत: सीएसडीएस द्वारा संचालित 2019 का राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन.

दलितों में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक विरोधी भावनाएँ हैं। जिन दलितों में अल्पसंख्यक-विरोधी भावनाएँ ज़्यादा थीं उन्होंने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया। अल्पसंख्यक विरोधी भावना रखने वाले 38 प्रतिशत दलितों ने भाजपा को वोट दिया। (तालिका-11)।

विरोधी' माना गया. 0 अंक पाने वाले के बारे में यह माना गया कि उसका अभी तक कोई ठोस विचार नहीं है.

तालिका-10

	अत्यंत अल्पसंख्यक विरोधी	अल्पसंख्यक-विरोधी	अल्पसंख्यक समर्थक	अत्यधिक अल्पसंख्यक समर्थक	कोई वचनबद्धता नहीं
उच्च जाति	8	14	36	40	3
अन्य पिछड़ी जाति	9	14	37	36	4
अनुसूचित जाति	11	15	33	35	5
अनुसूचित जनजाति	12	12	33	37	6
मुस्लिम	11	13	23	51	2
अन्य	13	18	22	43	4
	10	14	33	39	4

तालिका-11

	कॉन्ग्रेस	कॉन्ग्रेस के सहयोगी	भाजपा	भाजपा के सहयोगी	बसपा और सहयोगी	वाम दल	अन्य
अत्यंत अल्पसंख्यक विरोधी	14	2	38	4	8	4	30
अल्पसंख्यक-विरोधी	22	8	27	9	10	3	21
अल्पसंख्यक समर्थक	18	5	34	15	10	2	15
अत्यधिक अल्पसंख्यक समर्थक	21	5	33	5	11	2	23
कोई वचनबद्धता नहीं	10	8	23	6	12	4	37

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भाजपा को विभिन्न चुनौतियों के बावजूद दलितों का वोट हासिल करने में कामयाबी मिली। असल में, उसने दलितों का सबसे ज़्यादा वोट हासिल किया। पारंपरिक रूप से जो दल दलितों या हाशिये पर पड़े समूहों के समर्थन का दावा करते थे, वे अपना वोट नहीं बचा पाए। भाजपा ने रणनीतिक रूप से सामाजिक नीतियों के लाभों का वितरण वंचित दलित तबक़ों तक किया, इससे उसे इन समूहों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। भाजपा द्वारा जाति के स्थान पर धार्मिक पहचान को मज़बूती देने की कोशिशों के कारण भी उसे दलितों का समर्थन हासिल करने में कामयाबी मिली।

संदर्भ

अमिताभ श्रीवास्तव (2018), 'हाउ नीतीश कुमार इज़ रिजिगिंग हिज़ दलित स्टैट्रजी, डेलीओ, अप्रैल 18, https://www.dailyo.in/politics/nitish-kumar-dalit-mahadalit-lok-sabha-2019-bihar/story/1/23543.html, देखने की तारीख़ : 31 दिसंबर, 2019.

क्रिस्तॉफ़ जैफ़्रलो (2012), 'द कास्ट इज़ बैस्ट मोज़ैइक ऑफ़ इंडियन पॉलिटिक्स', *सेमिनार,* 633.

ज्योतिप्रसाद चटर्जी और सुप्रियो बसु (2019), 'अ न्यू ट्रैजेक्टरी ऑफ़ पॉलिटिक्स इन वेस्ट बंगाल', *इकनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली*, 55 (31).

टाइम्स ऑफ़ इंडिया (2019), 'बीजेपी मेक्स डेंट्स इन द टीएमसीज़ मुस्लिम-दलित वोट बैंक, बैग्स 5 आउट ऑफ़ 10 एलएस सीट्स', 25 मई, https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/bjp-makes-dents-in-tmcs-muslim-dalit-vote-bank-bags-five-out-of-10-ls-seats/articleshow/69489775.cms देखने की तारीख़ : 1 जनवरी, 2020.

बद्री नारायण (2019), 'डिवाइडिड दे स्टैंड : व्हाई मार्जिनल दलित कास्ट्स स्टिल लैक पॉलिटिकल क्लाउट', *इकनॉमिक टाइम्स*, 24 मई, https://economictimes.indiatimes.com/articleshow/69476973.cms?

from=mdr&utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst देखने की तारीख़ : 3 जनवरी, 2020.

संजय कुमार और प्रणव गुप्ता (2019), 'व्हेयर डिड द बीजेपी गेट इट्स फ़ॉर्म इन 2019?', *लाइव मिंट*, : https://www.livemint.com/politics/news/where-did-the-bjp-get-its-votes-from-in-2019-1559547933995.html. देखने की तारीख़ : 3 जनवरी, 2020.

सुरूर अहमद (2018), 'नीतिश कुमार्स 'महादलित' डाइलेमा', *नैशनल हेराल्ड,* 11 मई, https://www.nationalheraldindia.com/india/nitish-kumars-mahadalit-dilemma देखने की तारीख़ : 30 दिसंबर, 2019.

सुहास पलशीकर (2007), 'दलित पॉलिटिक्स इन नाइनटीज़ : इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऐंड प्रेडिकामेंट बिफ़ोर ऐन अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटी', द *इंडियन जर्नल ऑफ़ सोशल वर्क*, 68 (1).

श्रेयस सरदेसाई (2019), 'द रिलीजियस डिवाइड इन वोटिंग प्रिफ़रेंसेज़ ऐंड एट्टीट्यूड्स इन द 2019 इलेक्शन', *स्टडीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स*, 7 (2).